[Shri C. T. Dhandapani]

the working class. If the Central Government is very much against the working class, they would have turned down the request of the employees, but they accepted the demands. All the Trade Union leaders or representatives were there. They were given air tickets and sent back from Delhi to Madras yesterday. The employees got more than what they wanted. Therefore, this Government is not against the working class.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: This is because of the Joint Committee. It is a simple thing; you don't understand. The working class' striking power is so powerful that they had to concede their demands. If there were no unity amongst them, no demand would have been conceded.

SHRI C. T. DHANDAPANI: I want to give you some information regarding the Neyveli Lignite Corporation. Even singly, the DMK got its demand in 1974 without the assistance of any political party. Normally the CPM never signs on any agreement...

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have to go on to the next item: you can continue omorrow.

18.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

NOTIFICATION UNDER CUSTOMS ACT, 1962

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): On behalf of Shri Maganbhai Barot, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. 134|80-Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 3rd July, 1980, together with an explanatory note regarding exemption to hessian based jute specialities when exported out of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon, under section 159 of the Customs Act, 1962. [Placed in Library. See No. LT—993|80]

18.01 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

ADDITIONAL FACILITIES TO FREEDOM FIGHTERS

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं 11 जून के अतारांकित प्रश्न संख्या 364 के उत्तर से उत्पन्न प्रश्नों के बारे में चर्जा उठा रहा हूं। जिस प्रश्न की मैं ने चर्चा की है वह प्रश्न मेरे ही नाम से था। इस प्रश्न के पहले मैंने 7 अप्रल, 1980 को प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उस में स्वतन्त्रता सेनानियों की कठिनाइयों के बारे में, उन की दिक्कतों के बारे में तेरह सूत्री मांग पत्र रखा था। उसी मांग पत्र के बारे में यह 11 जून का प्रश्न था। उसी प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह चर्चा शुरू कर रहा हूं।

देश के स्वतन्त्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां कीं, जिस प्रकार से देश को आजाद करवाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वह जग जाहिर है और उसी का प्रताप है कि हम और आप यहां स्वतन्त्र भारत में स्वतन्त्र संसद में बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों की कठिनाइयों के बारे में देश में तथा दोनों सदनों में बरसों से सवाल उठते रहे हैं जिस के परिणाम स्वरूप 1972 में भारत सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना चालू की .....

श्री नूल चन्द डागा (पाली) : कांग्रेस ने की थी।

श्री रामावतार शास्त्री : लेकिन इस के लिए बहुत आन्दोलन करना पड़ा था और हाउस के बाहर भी करना पड़ा था। आप ने मजबूर हो कर या सहमत हो कर इस को चालू किया।

इस योजना के तहत दो सौ रुपये की पेंशन प्रत्येक स्वतन्त्रता सेनानी को दी जाती है। सरकार का जो उत्तर, मेरे प्रश्न संख्या 1092 के सिलसिले में 19 मार्च को आया है उस में बताया गया है कि पेंशन पाने वाले सेनानियों की संख्या उस समय 1 लाख 17 हजार 925 थी और जिन की दरख्वास्तें नामंजूर कर दी गई, उन की संख्या 94 हजार 451 थी। आज उन की संख्या क्या है मुझे मालूम नहीं है। प्राय: सभी स्वतन्त्रता सेनानी बूढ़े हो चुके हैं। बुढ़ापे में जो कठिनाइयां किसी के साथ होती है वे उन सेनानियों के साथ भी है। तो इन कठिनाइयों को देखते हुए अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन ने 8-सूत्री मांग-पत्र भारत सरकार के सामने रखा और स्वतन्त्रता सेनानी संगठन की तरफ से प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से हमारा प्रतिनिति-मंडल भी मिला और उन के सामने 8 मांगें रखीं। 8 मांगों

में से कुछ महत्वपूर्ण मांगें मैं बताना चाहता हूं जो कि सरकार के पास हैं ।

पहली मांग है कि जनता शासन के दौरान स्वगित की गई स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन को बहाल किया जाये ।

यह ठीक है कि जनता पार्टी की सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी विरोधी नीति अपनाई थी, जिस का समर्थन कोई नहीं कर सकता और मैं उस का विरोधी हूं ।

एक माननीय सदस्य : आप की मदद थी, उनके साथ ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप यह नहीं जानते, आप को राजनीति छोड देनी चाहिये । आप को यह खबर नहीं है कि सी० पी० आई० कभी भी जनता पार्टी की सरकार के समर्थन में नहीं थी ।

एक माननीय सदस्य : आप अभी भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे ।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, 'हाऊ कैन आई ..

दूसरी मांग है कि स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना को सांविधिक मान्यता दी जाये।

तीसरी मांग है कि इस योजना का नाम बदलकर सम्मान पेंशन योजना रखा जाये । क्योंकि जनरल पेंशन बहुत तरह के लोग पाते हैं, दोनों पेंशनों को एक तरह से मिला देना उचित नहीं है। दोनों में फर्क होना चाहिये । इससे आप उन सेनानियों का सम्मान कर रहे है जिन्होंने आजादी की लड़ाई मे अपनी शानदार भूमिका अदा की है इसलिये उस पेंशन में और इसमें फर्क होना चाहिये ।

चौथी बात है कि पेंशन की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह की जाये, क्योंकि मंहगाई बहुत हो गई है । सन् 1972 की तुलना में आज मंहगाई काफी आगे बढ़ गई है ।

पांचवी मांग है कि 5000 रुपये जिनकी वार्षिक आय हो, उनको स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की राशि नहीं मिलेगी, इस बारे में हमारा संगठन चाहता है कि इस शर्त को हटा दिया जाये । कोई आमदनी की सीमा नहीं रहनी चाहिये । बहुत से सेनानी अभी भी कई कटेगरी के बचे हुए हैं, उनको भी स्वतंत्रता सेनानी माना जाये । कुछ जाली सेनानी भी हैं, उनके बारे में आप जांच कर सकते हैं । जांच-पड़ताल करने के बाद कार्यवाही करनी चाहिये । इसमें बड़ा गड़बड़झाला है, जिसको चाहा पेंशन बन्द कर दी । अगर भ्रष्टाचार का शिकार वह सेनानी नहीं हुआ, घूस नहीं दिया तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है। बहुत सारे हमारे सेनानी ऐसे हैं, जिन्होंने अंडर-ग्राऊंड रहकर देश की सेवा की है,लेकिन उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है । हमारे संगठन ने मांग की है कि अगर राष्ट्रीय नेता उसे प्रमाण-पत्र देते हैं तो उसको स्वीकार करना चाहि और ऐसे लोगों को भी पेंशन देने की बात पर विचार करना चाहिये । यह मांगें हमने रखी थीं ।

इसका जवाब 19 मार्च को हमारे ही प्रश्न के जवाब में तारांकित प्रश्न सं0 124 में दिया गया कि उपर्युक्त जो 8 मांगे संगठन की हैं, उन पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र निर्णय लिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि शीघ्र का क्या अर्थ होता है ? मार्च का जवाब है और अब हम जुलाई में प्रवेश कर गये हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सदन के सामने यह रखें कि इन मांगों के बारे में सरकार ने अब तक क्या विचार किया है ।

हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमारे दोनों सदनों में स्वतंत्रता-सेनानी सांसदो की संख्या 103 है । हमने प्रधान मंत्री को यह सूची दी है और उनसे निवेदन किया है कि वह इन सदस्यों में से एक कमेटी बना दें और सरकार जाली स्वतंत्रता सेनानियों के सवाल और दूसरे सवालो के बारे में इस कमेटी की राय से निणय ले । यह ठीक है कि सरकार के दफ्तरों में भ्रष्टाचार है, चाहे वह दिल्ली का दफ़्तर हो चाहे बिहार का दफ़्तर हो । भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश होनी चाहिए । सरकार कहती है कि कोई उदाहरण बताओ । हम उदाहरण तो बहुत दे चुके हैं । मैं बता सकता हूं कि बिहार मे कुछ अधिकारियों ने स्वतंत्रता-सेनानियों से घूस लेकर चार-चार मकान बनवा लिये हैं । उनसे एक हज़ार, दो हज़ार रुपये की घूस ली जाती है---पांच सौ रूपये से कम नहीं लिये जाते हैं । बेचारे सेनानी ग़रीब हैं । वे अपनी ग़रज़ में आकर पैसा भी दे देते हैं । इन बातों की रोकथाम होनी चाहिए ।

मैंने 7 अप्रैल को प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें इन आठ मांगों समेत तेरह मांगों का जिक्र किया है । उसी के जवाब के आधार पर हमने यह बहस शुरू की है । सरकार ने हमारे संगठन की आठ-सूत्री मांग पर विचार कर लिया होगा : मेरी चिट्ठी में जो तेरह-सूत्री मांग का जिक्र है, उसने उस पर भी विचार किया होगा । हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस सिलसिले में क्या करना चाहती है । क्या वह पांच हज़ार रुपये की आय की सीमा को समाप्त करना चाहती है या नहीं ? क्या वह 200 रुपये की राशि को बढ़ाना चाहती है या नहीं ? क्या वह स्वतंत्रता-सेनानियों को आयकर से मुक्त करने का विचार रखती है या नहीं ?

जहां तक औरतों का संबंध है, अगर किसी

[श्री रामावतार शास्त्री]

स्वतंत्रता-सेनानी की मृत्यु हो जाये, तो उसेकी पत्नी को केवल 100 रुपये दिये जाते हैं, जबकि उस स्वतंत्रता-सेनानी को 200 रुपये दिये जाते यह विभेद क्यों है ? औरतों को तो ज्यादा राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी आवश्यकतायें ज्यादा होती हैं, क्या सरकार औरतों को भी उनके मर्दों के बराबर पेंशन देने के लिए तैयार है ?

गांधी-इर्विन समझौते के जमाने के बहुत से सेनानी है । जिन्होंने पांच महीने तक सजा काटी है, उन्हें तो पेंशन दी जाती है । लेकिन कई लोग जेल में तीन चार या साढ़े चार महीने तक रहने के बाद गांधी-इर्विन समझौते के फलस्वरूप जेल से रिहा हुए थे । इसमें उनका कुसूर नहीं है । उन्हें क्यों दंडित किया जाता है ? हम लोगों की मांग है कि उन तमाम लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, अगर वे सही सेनानी हैं, तो । हमारा संगठन जाली स्वातंत्रता- सेनानियों के विरुद्ध है । इस बारे में ठीक तरह से जांच की जाये और जो पकड़ा जाये उसेको सजा दी जाये । उसकी सिफारिश करने वाले को भी सजा दी जाये । उस पर हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन सच्चे स्वतंत्रता-सेनानियों के साथ ठीक व्यवहार होना चाहिए ।

जब वे लोग दफ्तरों में जाते है, तो उन्हे लांछित और अपमानित किया जाता है । वे लोग हमारी राष्ट्रीय निधि है । जितने दिन वे जिन्दा रहेंगे, देश उनसे प्रेरणा लेकर आगे के कर्त्तव्यों को निर्धारित करता रहेगा, उनसे स्वतंत्रता को बचाकर रखने की प्रेरणा लेगा ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सब मांगों के बारे में सरकार का क्या विचार है और इस सिलसिले में वह क्या कार्यवाही करना चाहती है । जिन लोगों की पेंशन जनता पार्टी की सरकार के जमाने में बन्द कर दी गई थी, उनके बारे मे वह क्या करना चाहती है ? क्या उसने ताम्रपत्र देने का निश्चय किया है या नही, जिसे जनता पार्टी सरकार ने बन्द कर दिया था ? मैं इन सवालो का जवाब चाहता हू ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to remind the hon. Member, Shri Ramavatar Shastri Ji, that this Scheme was started on the 15th of August, 1972, by the present Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, when she was Prime Minister at that time also. It is because she has a great symapthy—and not only sympathy—love and respect for all the freedom-fighters, that she started this scheme.

SHRI HARINATHA MISHRA (Darbhanga): She herself is a freedom-fighters.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: As I said, she has got great respect for the freedom-fighters, and therefore she started this Scheme. I also agree with you that it was the Janata Party which stopped this freedom-fighter's pension scheme; for some time pensions have been stopped for some freedom-fighters. After we took over, under her instructions, we have given the pensions to those whose pensions were stopped. In many cases, we have reviewed. There are very many cases which we are reviewing at present.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can give the number if it is available.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I will give in course of time. In other cases also, wherever we have got representations from them, we are reviewing them.

The Freedom Fighters' Pension Scheme provides for the grant of pension of Rs. 200 per month for living freedom fighter and Rs. 100/- for widow if the freedom fighter is not alive. In the case of family pension additional amount of Rs. 50/- is sanctioned for every unmarried daughter subject to a total family pension of Rs. 200/- p.m.

Government are fully aware of the problems faced by the freedom fighters. The question of enhancement of their monthly pension of Rs. 200/- has been receiving our earnest consideration. The question of removal of the annual income ceiling of Rs. 5,000/- which was fixed in 1972 has also been receiving our consideration. In view of the heavy financial implications of a recurring nature involved in accepting these demands and difficulty of finding additional resources for meeting the enhanced expenditure on the Scheme, there has been some delay in taking decision. Government would do their best to expedite their decision

on these two issues which have been agitating the minds of the freedom fighters.

Government have given full consideration to the 13 points raised by the hon. Member in his letter to the Prime Minister. As the hon. Member is aware, the Home Minister has already replied to him on 13-6-1980. The Government have also given careful consideration to the demands submitted by the All-India Freedom Fighters' Organisation in February 1980. The two main demands, as already stated, are under examination. As regards other demands, Government have not been able to agree to the following:

(a) Statutory recognition of the Pension Scheme;

(b) Tax-free freedom-fighter pension;

(c) Recognition of the suffering in the Army Mutinies as part of the freedom struggle.

As regards other points raised by the hon Member in his letter to the Prime Minister, I would like to explain the position point-wise:

(i) Grant of pension to people released under Gandhi-Irwin Pact. Relaxation has been given to the extent of one month remission on 6 months' or more conviction. It has not been possible to relax any further.

(ii) Enactment of Central Legislation for providing medical facilities.

All the State Governments and Union Territories Administrations have their own Schemes and it has not been considered necessary for the Central Government to enact any legislation.

(iii) Restoration of suspended pension:

Pensions have been suspended on valid grounds and the individuals concerned are given opportunity to explain their position and adduce additional evidence. On its receipt their cases are reconsidered and pension restored in eligible cases.

(iv) Verification of bogus cases of Freedom Fighters:

The present procedure of getting complaints verified through the State Governments and sanctioning pension only on the basis of reports from the State Government seems to be adequate.

(v) Extension of last date for applications:

It has not been possible to agree to this since the Scheme has been in existence for the last nearly 8 years and people had ample opportunity to apply earlier.

श्री रामावतार शास्त्री : 31 मार्च 1974 तक ही समय था । आप 8 साल जोड़ रहे है ।

(*Interruptions*).

SHRI YOGENDRA MAKWANA:

(vi) Awarded to Tamra Patras:

Decision has been taken to continue the Scheme for award of Tamra Patras.

(vii) Publication of 'WHO'S WHO' of freedom fighters:

It may not be possible at this stage to compile such a list.

(viii) Visit of freedom fighters to the historical places once a year:

Due to heavy financial implication, it has not been possible to consider this demand.

(ix) Stoppage of corruption:

No action is possible on general and vague references.

Then he said about the re-naming the Scheme. It has been decided that the Scheme be renamed as "Swatantra Sainik Samman Pension Scheme". This was the name suggested by the All India Freedom Fighters Organisation.

SHRI C. T. DANDAPANI: I cannot understand the meaning of it.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Swatantra Sainik Samman Pension Scheme means "Freedom Fighters Pension Scheme". So, Sir, most of the demands we have considered and as I have said there are some financial implications. We have to refer it to the Finance Ministry and we have to go before the Cabinet also. Therefore, it takes some time and I have already replied to the Hon. Member that it is under consideration and it will be decided as early as possible.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr M. C. Daga, you can put only one question. This discussion must be over before 6.30 P.M.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने यह आश्वासन दे दिया था कि स्वतंत्रता सेनानियों की कमेटी ही इन मांगों पर विचार करेगी उसके बाद यह निर्णय लेने के पहले उस कमेटी को न बुलाकर और इसको स्टेट्यूटरी बॉडी न देकर आपने आगे के लिए यह रास्ता खोल दिया है कि स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन, कोई नयी पार्टी की सरकार आकर चाहे तो उसको बन्द कर दे। जब आप मानते हैं कि इसको स्टेट्यूटरी रिकग्निशन देना चाहिए और स्वतंत्रता सेनानियों की कमेटी बुलाकर, जो भी निर्णय वे लें उसको मानना चाहिए और स्वतंत्रता सेनानियों की कमेटी को ही मौका देना चाहिए कि किसी दरख्वास्त को वे ले सकें और अपना निर्णय दे सकें तो जो कोई करप्शन है उन्हीं यह आप उनके ऊपर ही छोड़ दें। स्टेट्यूटरी रिकग्निशन न देने का मतलब यही है कि अभी भी आप इस बात को खुला रखना चाहते हैं कि आगे कोई तो इसको बन्द कर दे। मैं जानना चाहता हूं आप कौन सी तारीख तक निर्णय ले लेंगे? फिक्स्ड डेट आप बतायें कि इस डेट तक आप निर्णय ले लेंगे।

SHRI NIREN GHOSH: Sir, I am not a person who will accept anything from the Government on account of my participation in the freedom struggle. They gave me Tamra Patra, but I rejected it. But for those who want this Pension Scheme to be included, I would like to plead for them. Delhi office has lately been telling us that our (S.A.C.) recommendation for political pension will not be accepted if it reached Delhi after 30-4-79. Delhi office has sought to apply such exclusions even to applications received at the Writers Building by 31-3-1974. But the Committee dealing with it could not perhaps send the same to you before 30-4-1979. Such cases are creating extreme difficulties. I think, you will kindly consider it. The delay in various cases is due to illness, which should be condoned on production of medical certificate. The delay for production of the annual income over Rs. 4999/- should also be condoned on production of retirement certificate etc Delay in respect of the illiterate people who plead ignorance to this scheme may also be condoned. All these require sympathetic consideration.

Then, in my part of the country many people have come over from Bangladesh. They are divorced from each other. It is very difficult for them to get co-prisoner certificates from those who have remained in the same prison. Some solution should be there for this.

Persons involved in the trade union and kisan movements before 1947 were also entitled to pension under this scheme, but somehow that was discontinued. They should also be included in this. That should be regarded as part of the anti-imperialist struggle.

Further, if some persons are still in Bangladesh and ultimately they are forced to come over here by any reason whatsoever, you should consider their cases at the appropriate time and should not regard their cases as time-barred.

I find that the co-prisoner certificates from the Ex-M.Ps are also not been accepted. This should be considered.

Lastly, I would like to point out that some mutiny cases are also there. All these mutinies did take place. The various cases are for example RIN, Chandersingh Garwal case, 21st Central India Horse, Empty Loading and Unloading case, Suez—Army Revolt, 1943 Artillery Army Revolt at Madras in 1943, Steel Hemlet case at Hong Kong—all these cases you should consider.

Finally, I reinforce the demand that has been made that you should change the figure of 200 to 500.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Shri Daga made a point for giving statutory status to this scheme. I would like to point out that this question has received full consideration earlier also at the time of introduction of the scheme. The then Minister, Shri K. C. Pant made a statement in the meeting of the Consultative Committee that we might try out the scheme, as implementation of a scheme of this kind gives us far more flexibility. If there is a statute, there will be rules and regulations with the result that the form of verfication would be stricter and all kinds of technicalities would come into operation. (*Interruptions*) .. If you give a statutory backing, then it will become just like a Government scheme for Government servants. Why do you want to denigrate the freedom fighters? We want to give them this pension with respect. We do not want to denigrate them to the status of Government servants... (*Interruptions*). They have rendered service to the nation; this scheme is out of respect towards them. We don't want to downgrade them to the level of Government servants. Therefore, the statutory backing is not there. (*Interruptions*) About the date, I cannot give a fixed date, because many formalities are to be followed. Some certificates are given, which are incomplete. In many cases—I can give you the number, if you want—they have simply sent the application saying: "I am a freedom fighter. Please sanction freedom fighters' pension to me." How is it possible to sanction pension on the basis of such applications? (*Interruptions*) There is no form. They have not supplied any information. (*Interruptions*)

SHRI MOOL CHAND DAGA: About the amount, which you want to increase, I want to know the exact date. By what date will you enhance the amount?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: That also is not within my powers. It is with the Finance Ministry. I have referred it to them. About financial implications, we have to refer it to the Finance Ministry. We have referred it to them. Then it will have to go to the Cabinet.

PROF. N. G. RANGA: How long will you take.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I cannot say. It is not my Ministry. I cannot say anything about the Finance Ministry. How can I say? I cannot say anything about it. I am not able to fix a date. These are the two questions of Mr. Daga.

About Niren Ghosh now. He pointed out that the last date for applications should be extended. The scheme is there in operation for the last 8 years.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: But the last date was 31st March 1974. (*Interruptions*)

SHRI MOOL CHAND DAGA: What about the formation of a committee of *swatantra senanis*, and that committee applying its mind to it and giving its suggestions?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I have taken note of the suggestion of Mr. Daga.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): The Prime Minister has said that... (*Interruptions*) a panel of freedom fighters for among M. Ps will be formed to help Government.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Prof. Ranga, the Prime Minister has said many things, and we are doing them. We are acting according to the instructions of the Prime Minister.

PROF. N. G. RANGA: No, no. Prime Minister has agreed to form a panel; and you are saying that you are cancelling them.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I have said that I have taken note of it. It does not mean that it has been cancelled. It is still there. Then about mutinies... (*Interruptions*).

SHRI NIREN GHOSH: Due to several reasons, e.g. the State body vetting these applications, they may reach you a little late. For that reason, you should not reject them.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: If it is received by any Government—State or Central—that date will be taken into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The date of receipt by the State Government will be taken into consideration. Now it is over. The half-an-hour discussion is over. The House stands adjourned.

18. 33 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 4, 1980/Asadha 13, 1902 (Saka).

GMGIPMRND—1070 LS—10-9-80—890